



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939

No. 120]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(विभाग वाणिज्य)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

मामला सं. एसएसआर-07/2017

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्सियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

सं. 07/01/2017-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्सियली ओरिएंटेड यार्न (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2007 की अधिसूचना 14/10/2005-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित की गई थी। जांच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2007 की अधिसूचना सं. 92/2007 द्वारा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. तत्पश्चात् प्राधिकारी ने दिनांक 11 फरवरी, 2011 की अधिसूचना द्वारा उक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की और अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 15/27/2010-डीजीएडी दिनांक 10 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की। सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 22/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 2 मई, 2012 द्वारा शुल्क की अवधि को आगे पांच वर्षों अर्थात् 1 मई, 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

3. यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि उससे पहले न हटाया जाए तो उनके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों के बाद वह निष्प्रभावी हो जाते हैं और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। उक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

4. और यतः मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक याचिका दायर की गई है जिसमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तु के पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए पार्सियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे पांच वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद पार्सियली ओरिएंटेड यार्न है जिसे आम तौर पर पीओवाई के रूप में जाना जाता है। यह निर्यात और आयात मदों के आईटी (एचएस) वर्गीकरण के सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 5402.46 के अधीन आता है। यह पालिस्टर का यार्न है और एक मध्यवर्ती वस्तु है जो आगे प्रसंस्करण उदाहरण के लिए टैक्स्ट्राजिंग या ड्रा ट्विस्टिंग, के अधीन होती है, ताकि उसे कपड़ों की बुनाई और निटिंग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।

6. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

7. आवेदक ने बताया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान वस्तु हैं। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. निर्णायक समीक्षा हेतु अनुरोध मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा किया गया है जो मै. इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लि., मै. जेबीएफ इंडस्ट्रीज लि., मै. गार्डन सिल्क मिल्स लि. और मै. आलोक इंडस्ट्रीज लि. द्वारा विधिवत रूप से समर्थित है। भागीदार कंपनियों और समर्थकों को संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। इसलिए, आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना गया है और क्षति जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अधीन भागीदार कंपनियों को घरेलू उद्योग माना गया है।

शामिल देश

9. लागू शुल्क चीन जन. गण के विरुद्ध है। अतः यह निर्णायक समीक्षा चीन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को कवर करेगी।

ख. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

10. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों संबंध में सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 22/2012-सीमाशुल्क दिनांक 2 मई, 2012 द्वारा लागू शुल्क को हटाये जाने से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के विरुद्ध लागू निश्चयात्मक शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

प्रक्रिया

11. इस समीक्षा में दिनांक 10 फरवरी 2012 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/27/2010-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्सियली ओरिएंटेड यार्न के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई थी।

12. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

जांच अवधि

13. याचिकाकर्ता द्वारा जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 (12 महीने) की जांच च अवधि का प्रस्ताव किया गया है। तथापि प्राधिकारी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने) की अवधि को जांच अवधि के रूप में मानते हुए जांच करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। क्षति संबंधी आकड़ों का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच अवधि के आकड़ों पर विचार किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 15, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

15. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

16. प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- क. कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ. विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

समय-सीमा

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ साफ्ट प्रति भी होनी चाहिए।

20. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता

उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

- 26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने कर सकते हैं। पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें

डा. इन्द्रजीत सिंह अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES), NEW DELHI

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

Case No. SSR-07/2017

(SUNSET REVIEW)

Subject : Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on import of Partially Oriented Yarn (POY), originating in or exported from China PR.

No 07/01/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Partially Oriented Yarn (POY), (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject Country). The final findings notification of the Authority was published vide notification 14/10/2005-DGAD dated 8th June, 2007. On the basis of the findings, definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notifications No. 92/2007 dated 03.08.2007.

2. Subsequently, the Authority initiated a sunset review of the above anti-dumping duty vide notification dated 11th February, 2011 and recommended continued imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from the above country vide Final Finding Notification No. 15/27/2010- DGAD dated 10th February, 2012. The duties were extended vide Customs Notification No. 22/2012-Customs (ADD) dated 2nd May 2012 for a further period of 5 years i.e., until 1st May 2017.

3. WHEREAS in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And whereas, a petition has been filed by M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as 'petitioner') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of Partially Oriented Yarn (POY) for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the above goods originating in or exported from China.

Product under Consideration

5. Product under consideration is Partially Oriented Yarn, generally known as POY. It falls under the Customs Tariff Heading 5402.42 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items. It is the yarn of Polyester and is an intermediate, which is subject to further processing, for example, texturing or draw twisting, to make it suitable for weaving or knitting into fabrics.

6. Present investigation, being a sunset review of the duty in force, the products under consideration would remain the same as has been defined in the original investigation.

7. Petitioner has submitted that the subject goods produced by them are like article to the goods imported from the subject country in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

Domestic Industry and Standing

8. The request for the sunset review has been filed by M/s. Reliance Industries Limited duly supported by M/s. Indo Rama Synthetics (India) Ltd, M/s. JBF Industries Limited, M/s. Garden Silk Mills Ltd, and M/s. Alok Industries Limited. The participating companies and the supporters account for a major proportion of the domestic production of the subject goods. Therefore, the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry and the above participating companies have been treated as the domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules for the purpose of injury investigation.

Country involved

9. The duties are in force against the People's Republic of China. Therefore, this sunset review will cover the duty in force on the subject goods originating in or exported from the China.

Initiation of Sunset Review

10. Having satisfied itself, on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, the Authority hereby initiates an investigation in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review whether revocation of the duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country, imposed vide Customs Notification No. 22/2012-Cus dated 2nd May 2012, shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from the subject country and continuation or recurrence of injury to the domestic industry, and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods originating in or exported from the subject country.

Procedure

11. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. 15/27/2010-DGAD dated 10th February, 2012 recommending continuation of Anti-dumping duty on import of Saccharin originating in or exported from China PR.

12. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Period of Investigation

13. The period of investigation was proposed as January 2016 to December 2016 (12 months) by the petitioner. However, the Authority considers it more appropriate to carry out the investigations taking into account the period of investigation as April 1, 2016 to March 31, 2017 (12 months). For the purpose of analyzing injury data, the data of previous three previous years, i.e., 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI will be considered.

Submission of Information

14. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy/representatives in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry in India are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce
Room No. 15, 4th Floor Jeevan Tara Building,
Parliament Street New Delhi-110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

16. While submitting the questionnaire response, producers/exporters in the subject country may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may provide sufficient information on the following:

- a. Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
- b. Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
- c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d. Change rate conversions are carried out at the market rate.

Time Limits

17. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need for continuation, or otherwise, of the Anti-dumping measures, within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Confidential Basis

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

20. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

21. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential, version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof, or without a good cause statement on the confidentiality claim, may not be taken on record by the Authority. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

25. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

26. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority